ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 439-440

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना

संगीता यादव
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, नेताजी सुभाष चन्द बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
देवगाँव–आजमगढ़ (उ0प्र0), भारत

Received- 12.07.2020, Revised- 15.07.2020, Accepted - 17.07.2020 E-mail: - hemantkumarasthana1955@gmail.com

सारांश : *'ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना का अध्ययन अनेक ग्रामीण समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया है। एस०सी० दुबे, एम०ए० श्रीनिवास, डी०एन० मजूमदार, बी०आर० चौहान, मैकिम मैरियट, सिंगर तथा रॉबर्ट रेडफील के नाम इन विद्वानों में उल्लेखनीय है। राबर्ट रेडफील्ड ने भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना का उल्लेख करने के लिए वह परिवार, नातेदारी, धर्म, जाति, शिक्षा, सत्ता एवं अर्थव्यवस्था आदि आधारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। डॉ० दूबे ने इनके अतिरिक्त मूल्य व्यवस्था को भी भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए आवश्यक माना है, हम रेडफील्ड तथा दूबे द्वारा प्रस्तुत आधारों को भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना को समझने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देना आवश्यक है कि यदि हम केवल रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत आधारों को ही कसौटी मानकर चलें तो भारत के विभिन्न ग्रामों की सामाजिक संरचना भी एक दूसरे से भिन्न दिखाई देगी। जिस गांव में एक जाति अथवा धर्म के लोग रहते हैं, वहां की सामाजिक संरचना उस गांव की सामाजिक संरचना से भिन्न होगी, जहाँ अनेक धर्मों और जातियों के लोग साथ–साथ रहते हैं। यदि हम केवल सामाजिक मूल्यों को ही आधार मानें तो विभिन्न क्षेत्रों की ग्रामीण सामाजिक संरचना में अत्यधिक भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि व्यावहारिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियाँ आज एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। इसका तात्पर्य है कि भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन सामान्य विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए, जो सभी क्षेत्रों में बहुत कुछ समान रूप से देखने को मिलती है।*

कुंजीभूत शब्द– ग्रामीण समाज, सामाजिक संरचना,ग्रामीण समाज, परिवार, नातेदारी, धर्म, जाति, शिक्षा, व्यावहारिक।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय ग्रामीण संरचना में तीव्र रूपान्तरण की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। रूपान्तरण की इस प्रक्रिया में औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, यातायात तकनीक में परिवर्तन, भूमि सुधार, कृषि भूमि परिसीमन, हरित क्रान्ति, कृषि विकास से सम्बन्धित नवीन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, उच्च कृषि उत्पादन के साथ–साथ नवीन बाजार व्यवस्था की वैचारिकी ने सक्रिय योगदान दिया है। ग्रामीण समाज में उत्पादन सम्बन्धों के आधार पर किये गये शक्ति समूह, राजनीतिक संगठन और संगठित मांगों के प्रारूप पर स्थापित हुए हैं।

भारतीय ग्रामीण समाज में उच्च– कृषक वर्ग राजनैतिक शक्ति के रूप में सामने आए हैं। ग्रामीण संरचना और उत्पादन सम्बन्धों पर विभिन्न समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक–अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष यह प्रस्थापित करते हैं कि भारतीय ग्रामीण संरचना क्षेत्रीय विविधताओं से परिपूर्ण हैं और अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग उत्पादन सम्बन्ध व विधायें निहित हैं। त्रिपाठी (1991) द्वारा भारतीय ग्रामीण संरचना के समग्र रूपान्तरण की दशाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। जिसके अन्तर्गत उपनिवेशकालीन एवं वर्तमान ग्रामीण संरचना के आधार पर अधि– विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और शक्ति क्षेत्रों में विभिन्नताएं निहित हैं। उपर्युक्त आधार पर वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत क्षेत्र की ग्रामीण संरचना की विशिष्टताओं एवं यथास्थिति का विवेचन किया गया है।

भारतीय ग्रामीण संरचना के सन्दर्भ में थार्नर (1956) द्वारा किया गया अध्ययन प्राथमिक विशिष्ट कोटि का अध्ययन था। थार्नर ग्रामीण संरचना और सम्बन्धों को विवेचित करते हुए ग्रामीण समाज और मूलतः कृषक समाज की समस्याओं का विवेचन किया है। उनका कथन है कि भारतीय कृषक संरचना विभिन्न वर्गों के मध्य निहित अन्तर्सम्बन्धों के लचीले जाल की भांति है। थार्नर और थर्नर (1962) ने कृषक संरचना में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि ग्रामीण भारत में परिवार अत्यन्त मिश्रित प्रकृति के हैं। अतएव सम्पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया को समग्रता के दृष्टिकोण से मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं की विविधता है और अलग–अलग परिवार अलग–अलग आर्थिक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

क्रियाओं में संलग्न है। साथ ही साथ भारत के बहुआयामी ग्रामीण संरचना में अलग–अलग क्षेत्र की कृषि व्यवस्था और उन क्षेत्रों में कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के साथ सम्बन्ध विभिन्न अवधारणाओं से सम्बन्धित किए जाते हैं और उनके सम्बन्धों के अभिप्राय भी अलग–अलग हैं।

हरित क्रांति के साथ–साथ औद्योगिक क्रांति के गतिशील प्रभावों ने भारतीय ग्रामीण संरचना को अत्यधिक प्रभावित लिया है। थार्नर और थर्नर ने 1950 से 1962 के मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषक स्थिति का विवेचन किया है तथा उक्त विवेचन में परिवर्तन का विभिन्न शक्तियों यथा भूमि परिसीमन, भूमि सुधार, जनसंख्या दबाव, रेल सड़क परिवहन बाजार अर्थव्यवस्था, उच्च उत्पादकता वाले बीज एवं फसलें तथा प्रौद्योगिकी क्रांति का मूल्यांकन किया है, परन्तु थार्नर के बाद सम्पूर्ण भारतीय कृषक व्यवस्था और कृषक संरचना के सन्दर्भ में किए गए अधिकांश अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित रहे हैं। कृषक जनगणना प्रतिवेदन और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण संरचना के संदर्भों में निश्चित प्रकाश पड़ता है।

मिश्रा (1983), विरजिनस (1980), धनागरे (1983) और त्रिपाठी (1991) के अध्ययनों के साथ–साथ ओम्बेट (1980), शिवकुमार (1978), रुद्रा (1978) आदि के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषक संरचना अत्यधिक जटिल है और इसके शक्ति केन्द्रों के आधार हेतु किसी एक कारक को प्रमुख स्वीकार करना उचित नहीं है। कृषक संरचना में निहित शक्ति केन्द्र विभिन्न कारकों के प्रतिफल होते हैं। भारतीय कृषक संरचना के मूल आयामों के विवेचन के लिए जिन प्रमुख मुद्दों को आधार बनाया गया है उनमें कृषकों और ग्रामीण परिवारों में भू–स्वामित्व की प्रकृति, जाति आधार पर, भूमि वितरण, जोत आकार की स्थितियां कुल कृषि उत्पादों के विक्रय की स्थिति भूमि क्रय एवं विक्रय, कृषि उत्पाद और पारिवारिक सकल आवश्यकता में सम्बन्ध कृषि से कृषकों की संतुष्टि और असंतुष्टि तथा कृषक और कृषि श्रमिकों के अन्तर्सम्बन्ध के साथ–साथ आधुनिक कृषि संसाधनों के उपयोग की स्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

विश्वनाथन (1975) ने कृषि भूमि परिसीमन और सामाजिक गतिशीलता के अन्तर्सम्बन्धों का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भूमि सुधार की रणनीति ने मध्यवर्गीय कृषक परिवारों की उर्ध्वगतिशीलता को प्रभावित किया है। राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार की योजनाएं अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं।

सिन्हा (1075) ने भूमि सुधार के राज्य सरकार द्वारा किए जाने वालों प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भूमि सुधार योजना का मूल उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि वितरण और अत्यधिक भू–संकेन्द्रण केन्द्रों से भू–विस्थापना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

पार्थ सारथी और प्रसाद (1979) का कथन है कि कृषि की नवीन तकनीकी ने कृषक संरचना को अत्यधिक प्रभावित किया है। नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और कृषक सम्बन्धों की परम्परागत स्थिति में परिवर्तन किया है। इस संदर्भ में गंगा राव (1980), चट्टोपाध्याय (1982), भल्ला (1983) आदि के अध्ययन उल्लेखनीय हैं। धनागरे (1985) ने कृषि संरचना के महत्वपूर्ण आयामों का विवेचन करते हुए तेलंगाना के ग्रामीण परिवेश में हुए कृषक आन्दोलनों के आधारों, रणनीतियों एवं प्रतिफलों का मूल्यांकन किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. T. Tripathi, S.D. (1991) Transformation of Indian Agrarian Structure and Peasantry. Op Cit. See also of the same author (1990). De velopment Parandigms and Social Move ments. The Indian Context. The Journal of Sociological Studies, Vol. 9, pp. 120-129.
2. Thorner, D. (1956). The Agrarian Prospects in India, University Press Delhi.
3. Thorner, D. and Alice Thorner. (1962) Land and Labour in India, Asia Publ. House, Lon don, p. 26.
4. Ibid.
5. Mishra, G.P. (1983) The Village as a Unit of Investigation, Social Scientist, Vol. 11, No. 6, 61-67.
6. Virginius, X (1980) Evolution of Agrarian Structure and Class relations in Jalmaigun District (West Bengal), Sociological Bulletin. Journal of Indian Sociological Society, Vol. 29, No. 1, pp. 63-83.
7. Dhanagare, D.N. (1983), Prasant Movement in India, Oxford University, Bombay.
8. Omvedt, G. (1980) Caste Agrarian Relations and Agrarian Conficts. Sociological Bulletin Journal of the Indian Sociological Society. Vol. 29, No. 2, pp. 142-169.
9. Shiva Kumar (1978), Op cit.
10. Rudra, A. (1978) Class Relations in Indian Agriculture, EPW, Vol. 16, No. (3.10.17 June).

*****